

# दि कार्मिक पोर्ट

2020  
HAPPY NEW YEAR

वर्ष : 5, अंक : 19

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 1 जनवरी से 7 जनवरी 2020

पेज : 4 कीमत : 3 रुपये

## अमेजन के जंगल की अंधाधुंध कटाई



इस वर्ष में रॉयल स्टेटिकल सोसायटी के निर्णयिक मंडल में पिछले 10 वर्ष के सारियकी आंकड़ों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मैं भी मौजूद था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के %वर्ड ऑफ द इयर% की तरह यह प्रतिस्पर्धा दशक के सबसे जरूरी मुद्दे पर प्रकाश डालने वाले आंकड़ों के लिए है। 23 दिसंबर को हमने विजेता का ऐलान किया। अमेजन के जंगल से आये आंकड़े सबसे अधिक विचलित करने वाले थे। पिछले 10 वर्ष में 84 लाख फुटबॉल मैदान जितना जंगल समाप्त हो गया। यह आंकड़ा इस मुद्दे को ऊपरी तौर पर बताने के साथ पिछले 10 वर्ष में जमीन के ऊपर हुए बदलाव को भी काफी गहराई से बताता है। पिछले 10 साल में मील के मील वर्षावन की जगह व्यावसायिक विकास ने ले लिया। इस विकास में पाम ऑइल के कारखाने और पशुपालन के लिए बने मैदान भी शामिल हैं।

जंगलों की कटाई आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, कई बजहों से महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है की इन जंगलों में 2 से 3 करोड़ लोग निवास करते हैं और वर्षावन पर निर्भर हैं। इसके अलावा ये जंगल हजारों पेड़ पौधे और जानवरों का घर हैं, जिनमें से कई

विलुप्ति की कगार पर हैं। विश्व में मौजूद साफ पानी का पांचवा हिस्सा इन जंगलों से आता है, जो वाष्णवीकृत होकर वर्ष के रूप में हजारों मील दूर-दूर तक दुनिया के अन्य स्थानों तक पहुंचता है। ब्राजील में इस दशक

आया अभूतपूर्व सूखा के पीछे की वजह भी अमेजन जंगल की कटाई ही है। सूखे के दौरान साओ आउलो राज्य के किसानों ने कहा कि पानी की कमी की वजह से उनकी एक तिहाई फसल खराब हो गई। सरकार ने कॉफी से जुड़े व्यवसाय करने वालों को 300 मिलियन डॉलर की मदद देने का वादा भी किया। अमेजन के वर्षावन 18 हजार करोड़ टन कार्बन को सहजने की क्षमता रखते हैं। जब पेड़ को हटाया या जलाया जाता है तो यह कार्बन दोबारा वातावरण में वापस आ जाता है। शोधों से पता चलता है कि कार्बन उत्सर्जन की वजह से सामाजिक व्यव

10 साल में  
कटा 84 लाख  
फुटबॉल मैदान  
जितना जंगल

ब्राजील झेल रहा सूखा, किसानों  
को फसल भी हुई तबाह

417 डॉलर प्रति टन का होता है। नवम्बर 2018 का एक शोध दर्शाता है कि अमेजन को बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो यह मेरे, रबड़ जैसे सैकड़ों उत्पादों के साथ पर्यावरण कीमत होती है एक हजार डॉलर। जंगल की कटाई के बाद इन स्थानों और मुख्य रूप से मांस बाजार के लिए पशुपालन का काम होता है। ब्राजील में लगभग 20 करोड़ पालतू जानवर हैं। एक एकड़ पर दो गाय मान लें तो यह फायदा दो करोड़ का हुआ। किसानों, वाणिज्यिक हित सम्हूं और सस्ती जमीन की तलाश करने वाले अन्य सभी के पास वनों की कटाई में स्पष्ट निहित स्वार्थ है, लेकिन किसी भी संभावित अल्पकालिक लाभ को दीर्घकालिक नुकसान स्पष्ट रूप से अधिक चिंताजनक है। हर एक मिनट में अमेजन 3 फुटबॉल मैदान जितना वर्षावन खो रहा है। अगर कोई उन खोए हुए बनों को वापस लगाना चाहे तो क्या होगा? कई संस्थाएं इसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही हैं। दो हजार डॉलर में एक एकड़ जमीन इतनी सस्ती नहीं जब हमें पता हो कि खोए हुए जंगल को वापस उगाने में 300 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। मैंने अबतक जो शोध देखे हैं उससे पता लगता है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है।

लिबर्टी विटर्ट, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस ऑफ डेटा साइंस के प्रोफेसर हैं। यह लेख क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत प्रकाशित किया गया है।

# जलवायु पतन के लिए किया जाएगा याद

वर्ष 2010 में विकासशील देशों ने विकसित देशों के ऊपर कार्बन डेट (उत्सर्जन की सीमा तय करने वाले ऋण) को खत्म कर दिया। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के सबसे बड़े भुक्तमोगी होने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने को लेकर सहमतियां बनाते रहे। वे जलवायु संकट की जट्ठत और परिस्थिति की गंभीरता को समझे बिना ही उत्सर्जन बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाते रहे। विकसित देश हमेशा से ऐसी दिशा ही चाहते थे।

वर्ष 2010 में हुए कानकुन बैठक में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन के दौरान तय वैश्विक उत्सर्जन मापदंड मी अपना प्रभाव खोता गया। बहुदेशीय कोशिश होने के बदले जलवायु पर होने वाली चर्चाएं जलवायु के साथ समझौता बनकर ही रह गई हैं।

वैश्विक नेताओं ने कानकुन समझौते की काफी प्रशंसा की थी, बावजूद इसके कि यह समझौता विकासशील देश के वैश्विक कार्बन क्षेत्र तक समान पहुंच से विचित रख तरकी में बाधक था। कानकुन समझौते ने जलवायु परिवर्तन के भावावह प्रभावों से बचने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा निर्धारित 2 ए ए से नीचे औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैस की कमी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया। इस समझौते ने वैश्विक तापमान को

2 डिग्री सेल्सियस या इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की बात कही थी। हालांकि इसके लिए कोई रास्ता नहीं सुझाया गया था। इस समझौते में विकसित देश के लिए उत्सर्जन का कोई मापदंड तय नहीं किया हुआ था, साथ ही उस वर्ष का जिक्र भी नहीं हुआ था।

जब वैश्विक उत्सर्जन चरम पर होगा और जिस वर्ष के बाद इसमें कमी दिखना शुरू हो जाएगा। उल्टा यह समझौता अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान कर गया। कोपेनहेगन समझौते में उल्लिखित स्वैच्छिक प्रतिज्ञा और समीक्षा को कानूनी रूप दिया गया है। अब देशों को प्रतिज्ञाओं के रूप में अपने स्वयं के घरेलू लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति है। विकसित देशों की प्रतिज्ञाओं की माप, रिपोर्ट और सत्यापित किया जाएगा, लेकिन वे नहीं मिलने पर दंड या जुर्मान की गुंजाइश भी नहीं बचती। कानकुन समझौते ने जलवायु परिवर्तन से हमेशा के लिए निपटने के बुनियादी नियमों को भी बदल दिया और इसके बाद उत्सर्जन में कमी के बोझ को विकसित देशों से विकासशील देशों के ऊपर थोप दिया है।

विकसित देशों के कमजोर प्रतिज्ञा के खिलाफ विकासशील देशों ने अपने देश के उत्सर्जन को कम करने की गंभीर प्रतिज्ञा ली है। इसके तहत भारत ने वर्ष 2005 के मुकाबले 2020 तक उत्सर्जन को 20 से 25 प्रतिशत कर करने की बात कही थी। जिन औद्योगिक देशों को उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन में कटौती करके पीछा छुड़ा रहे हैं। उन्होंने 2020 तक 0.8 से लेकर 1.8 की कटौती की, विकासशील देशों ने 2.8 से अपने उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया। इन लक्ष्यों को पूरा करने की कीमत गरीब देशों के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। यह संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में बाधा बन सकता है, जिसमें भूख और गरीबी का उम्मलन और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है। अमेरिका जो कि अभी तक कटौती की घोषणा करने ही बाला है, को इस समझौते से सबसे अधिक फायदा मिल रहा है।

ऐतिहासिक तौर पर सबसे अधिक उत्सर्जन में कटौती कर लिए 40 प्रतिशत तक उत्सर्जन में कमी को आवश्यकता होगी, लेकिन 1990 के स्तर से तुलना करके देखें तो



बोलिविया एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस असमानता को झंगित किया था। इस देश के राजदूत पाल्लो सोलोन ने इस समझौते से अपने पांच पीछे खीचे थे तो अन्य लोगों ने इस बात की सहाहना भी की थी। औद्योगिक देशों के साथ कुछ उनरते हुए देशों ने जलवायु परिवर्तन पर हो रही वार्ता, विज्ञान और समाजता के सिद्धांत को ताक पर रखकर सबसे बड़ा तथ्यापलट किया था।

यह कमी शून्य प्रतिशत की ही है। वैश्वभर के नेताओं ने कागज पर तो वैश्विक गर्मी को 2 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धताएं दिखाई, जिसे गर्मी बढ़ने का सुरक्षित मापदंड माना गया है, लेकिन कोपेनहेगेन में किये गए बादे या फिर कानकुन में कानून बन जाने के बाद जितना उत्सर्जन काम करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है वह गर्मी को कम करने में काफी नहीं होगा। अगर देश अपनी प्रतिबद्धता पर कायम भी रहते हैं तो वैश्विक तापमान 3 से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे।

छोटे द्वीप और देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सबसे ज्यादा खतरा है, यह तक ??कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अधिक है और ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित होनी चाहिए।

कानकुन में क्या हुआ?

कानकुन में ऐसा क्या हुआ कि गरीब और सबसे अधिक खतरा खेल रहे देश जो 2009 में हुए समझौते के विरोध में थे, कानकुन के समझौते पर राजी हो गए?

यह समझने के लिए कि कोपेनहेगेन में और कोपेनहेगेन और कानकुन समझौते के बीच की अवधि में क्या हुआ, यह समझना होगा। अमेरिका की घरेलू राजनीति की बजह से भारत और चीन जैसे देशों की पूर्ण और पूर्ण भागीदारी के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौते की मांग सामने आई। इसका मतलब यह था कि अमेरिका अब दो-तरफा हस्तशृष्ट वार्ता जारी नहीं रख सकता था और उसे एक ऐसे समझौते की जरूरत थी जिससे उत्सर्जन काम करने की कोई कानूनी प्रतिबद्धता न हो और ऐसा ही समझौता भारत और चीन जैसे देश के साथ भी किया गया। यह कोपेनहेगेन समझौते की उत्पत्ति थी।

2017 के दशक में ये थी

25वें वर्ष के मील के पत्थर तक पहुंचता है, लेकिन इससे यह तय होता है कि कितनी दूरी तय की गई, यह तय नहीं होता है कि यहां तक पहुंचने में रफ्तार क्या थी। इस सदी की सबसे बड़ी विकासात्मक चुनौती-जलवायु परिवर्तन से निपटने में यह कन्वेशन अभी भी संघर्ष ही कर रहा है।

2019 के दशक में ये थी

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति प्लेटफॉर्म (आईपीबीईएस) द्वारा पहली बार वैश्विक आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 लाख पशु और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, और इसकी जवाबदेही केवल मनुष्यों पर ही आती है।

एक दशक के भीतर,  
चरम और विषम मौसम,  
उस दशक में नया  
सामान्य हो गया जो  
अभी-अभी गुजरा है।  
2011 से 2015 की पांच  
साल की अवधि विश्व  
स्तर पर सबसे गर्म रही।  
आलम यह है कि 2015  
का औसत तापमान  
औद्योगिक काल से शुरू  
होने से पहले के मुकाबले  
1 डिग्री अधिक बढ़ गया।  
इस बात की आशंका बढ़  
रही है कि 2015 का यह  
अधिकतम तापमान  
2030 तक सामान्य  
माना जाने लगेगा।  
2019 के पहले नौ महीने  
तक गर्मी ने अपने सभी  
रिकॉर्ड तोड़ दिए।

# अतिशय मौसम की घटनाएं बढ़ीं

2010 से 2019  
के दशक के  
दौरान मौसम  
इतनी बार चरम  
पर पहुंचा कि  
यह अब सामान्य  
लगने लगा



इस दशक में जलवायु परिवर्तन शब्द  
को जलवायु आपातकाल की संज्ञा दे दी  
गई। विश्व मौसम संगठन के अनुसार,  
चरम मौसम की घटनाओं के कारण 2019  
में 2 करोड़ 20 लाख लोग विस्थापित  
हुए। जो दुनिया भर में चल रही हिंसक  
घटनाओं के मुकाबले अधिक हैं। डाउन टू  
अर्थ के मार्च 2015 के अंक में इसका  
विस्तृत ब्यौरा दिया गया।

पश्चिमी विक्षेपित कम दबाव वाले क्षेत्र  
में जो कि वेस्टरलीज में स्थित हैं, ग्रह की  
हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर 30 डिग्री  
और 60 एडग्री अक्षांश के बीच बहती है।  
वे आमतौर पर जनवरी-फरवरी के दौरान  
हल्की बारिश लाते हैं, जो रबी की फसल  
के लिए फायदेमंद है।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी  
विक्षेपित को आपातकाओं से जोड़ा गया है।  
2010 में लेह में बादल फटने, 2013 में  
उत्तराखण्ड में बाढ़ और भूस्खलन और  
2014 में जम्मू-कश्मीर में अत्यधिक  
बारिश, ये सभी इन गड्बड़ियों से जुड़े थे।  
इस वर्ष, भारत मौसम विज्ञान विभाग के  
अनुसार, 1 मार्च से 18 मार्च के बीच  
औसत बारिश 49.2 मिमी -197 प्रतिशत  
सामान्य से अधिक थी। इससे देश के कई  
राज्यों में फसलों को गंभीर नुकसान हुआ।

दूसरा, एक अन्य अध्ययन के अनुसार,  
जो ग्लोबल वार्षिक को दोषी ठहराता है,  
वह न्यू जर्सी के रटगर्स विश्वविद्यालय के  
जेनिफर कर्फीस और अमेरिका में

## किस रास्ते से हवा चलती है

10 हेक्टेयर (हेक्टेयर) में फैली गेहूं,  
सरसों, चना और मेंढी की फसलों का  
नजारा विद्याधर ओलखा के दिल को  
खुशी से भर देगा। यह फरवरी के अंत  
में था और फसलें तैयार होने के लिए  
लगभग तैयार थीं। एक हप्ते बाद, उसके  
पास जमीन पर पढ़ी पतियाँ और डंठल  
की एक चटाई थी। मार्च के पहले सप्ताह  
में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने राजस्थान  
के झुंझुनू जिले में उनकी 70 प्रतिशत  
फसल को नष्ट कर दिया। ओलखा को  
पता नहीं है कि इस मार्च में इनकी बारिश  
वर्षों हुई। इस वर्ष न तो वैज्ञानिक और  
न ही मौसम के पूर्णनुमानकर्ता ने इसकी  
भविष्यवाणी की थी।

यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन के  
एस जे वाक्स द्वारा किया गया है।  
पर्यावरण अनुसंधान पत्र के जनवरी अंक  
में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि  
आर्कटिक के गर्म होने से उत्तरी गोलार्ध में  
जेट स्ट्रीम कमजोर हो गई है।

उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम के पश्चिम  
से पूर्व प्रवाह भूमध्य रेखा के पास शांत  
आर्कटिक और गर्म क्षेत्रों के बीच 'गर्मी  
की ढाल' द्वारा बनाए रखा जाता है।  
लेकिन आर्कटिक पिछले 20 सालों से गर्म  
रहा है जिसकी बजह से जेट स्ट्रीम  
कमजोर हो गई है। अपेक्षाकृत सीधे रास्ते

## दो हवाओं का संगम साल भर रहता है

घटना में परिवर्तन के पीछे के कारणों पर  
वैज्ञानिकों में कोई एकमत नहीं है। वे कई<sup>1</sup>  
तरह के स्पष्टीकरण देते हैं। मौसम विभाग के  
अनुसार, इस वर्ष की भारी बारिश पश्चिमी  
विक्षेपित और बंगाल की खाड़ी से आने वाली  
लहर के संगम का परिणाम है। इंस्टर की  
लहर, या इंस्टरलीस, पूरे वर्ष पूर्व से पश्चिम  
तक चलती है। दो हवाओं का संगम साल भर  
होता है, लेकिन परिणाम अलग-अलग होते  
हैं। विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वनुमान केंद्र  
के प्रमुख वी पी यादव कहते हैं, वे आम तौर  
पर देश के उत्तरी हिस्से में ही बारिश लाते हैं,  
लेकिन इस साल मध्य और दक्षिण भारत के  
राज्यों में भी बारिश हुई। उदाहरण के लिए,  
मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 1-18 मार्च  
के दौरान सामान्य से अधिक 2,025 गुना  
अधिक बारिश हुई, जबकि मध्य महाराष्ट्र में  
बारिश सामान्य से 3,671 गुना अधिक है।

में चलकर लगाने के बजाय, जेट स्ट्रीम अब  
मेन्डियर हो जाती है। इस बजह से दक्षिण  
क्षेत्र ठंडा और उत्तरी क्षेत्र गर्म बना रहा।  
फॉर्सिस का कहना है कि इन जेट स्ट्रीम से  
पश्चिमी विक्षेपित निश्चित रूप से प्रभावित  
हो सकता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल  
वेदर साइंस, पुणे के एक अध्ययन ने  
पश्चिमी विक्षेपित को सीधे ग्लोबल वार्मिंग  
से जोड़ा है। फरवरी 2015 में क्लाइमेट  
डायानामिक्स में प्रकाशित एक पेपर में,  
शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्लोबल  
वार्मिंग हवा की धाराओं को प्रभावित कर

रही है और सनकी मौसम की घटनाओं  
का कारण बन रही है।

अध्ययन के अनुसार, 1950 के दशक  
के बाद से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सतही  
तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षेत्र के  
अवलोकन हाल के दशकों में वर्षा में  
उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। शोधकर्ताओं ने  
भारी वर्षा की बढ़ती आवृत्ति को समझने  
के लिए विभिन्न प्रकार के जलवायु डेटा  
को देखा। वे कहते हैं कि उप-  
उष्णकटिंबरीय (कर्क रेखा और मकर  
रेखा के बीच का क्षेत्र) और मध्य अक्षांशों  
के मध्य और ऊपरी-झोभमंडलीय स्तरों में  
तापमान में वृद्धि हुई है। शोधकर्ताओं में से  
एक आर कृष्णन कहते हैं कि हमारे  
अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमी  
विक्षेपित की बढ़ती परिवर्तनशीलता का  
कारण मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन ही  
है।

## दशक 2012 की घटनाएं -

इस वर्ष ने कई रिकॉर्ड बनाए। गुगल सर्च से पता  
चलता है कि यह अमेरिकी इंडियन में सबसे गर्म वर्ष  
था और इन में दूसरा सबसे बड़ा वर्ष था। सयुक्त  
राष्ट्र की 2012 की एक रिपोर्ट कहती है कि  
लगातार लीसर साल मौसम की दरम घटनाओं के  
कारण 100 वित्तियन डॉलर से अधिक का आर्थिक  
नुकसान हुआ है।

## दशक 2019 की घटनाएं -

जब से फहली बार अंतरिक्ष विस्थापन नियमानी को  
ने 2018 में आपदाओं से विस्थापित हुए व्यक्तियों पर  
डेटा एकत्र करना शुरू किया है, जिससे यह  
समूह बढ़ रहा है। 2019 में, आपदाओं से विस्थापित  
16 लाख लोग अब भी शिविरों या घरों से बाहर थे।  
इससे पहले 2018 में अकेले भारत में 26.78 लाख  
लोग आपदाओं और मौसम की वर्षा घटनाओं से  
विस्थापित हुए, जो दुनिया में सबसे अधिक थी।

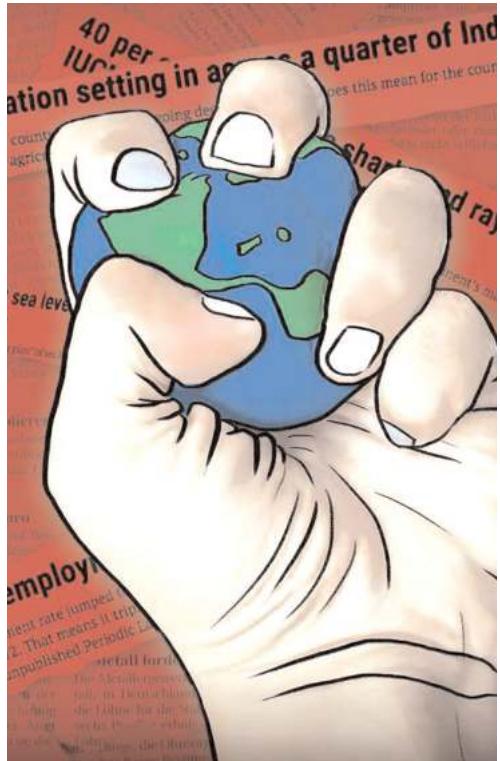
# विस्फोटक दुनिया में हम

दशक का अवसान हो गया है और उम्मीद है कि एक नई सुबह होगी। 2010-2019 के जिस दशक को हम अपने पीछे छोड़ रहे हैं, उसमें नेताओं की छवि धूमिल हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ी है और हर तरफ संघर्ष व गुस्सा नजर आया। इस दशक में हमने महसूस किया कि जलवायु परिवर्तन भविष्य की बात नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी गंभीरता बढ़ेगी। तापमान में वृद्धि और घरम मौसमी घटनाओं के मामले में इस दशक के हर साल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। गुजरा दशक केवल मौसम से संबंधित नहीं रहा। लेकिन, बात सिर्फ मौसम की नहीं है। इस दशक ने यह भी बताया कि दुनियाभर में लोग अपने वर्तमान और भविष्य को किस तरह देखते हैं।

हम जानते हैं कि संभवतः पिछले किसी भी दशक के मुकाबले आज युवा ज्ञादा बेचैन हैं। अमेर मुल्लों में युवा वर्ग चौकन्ना और अनिश्चितताओं से घिरा है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि इस गर्म होती दुनिया में वे कैसे खुद को बचाए रखेंगे। इसके साथ ही युवा अपनी नौकरियों को

लेकर भी चिंतित हैं क्योंकि उनके देश की समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं भी अब कुशल मजदूरों को हटाने लगी हैं। अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई यानी कृत्रिम बौद्धिकता) सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यह सक्षम नहीं होगा। ये एआई म्यूटेंट की तरह हैं, जिसका अपना जीवन होता है। यह पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा देख रहे हैं कि उनके आसपास की दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। उनके किसान पिता दो जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। खाद्यान उत्पादन में दाम और मौसम का जोखिम बढ़ रहा है और हर मौसम के साथ उन पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। अतः इसमें कोई आश्र्य नहीं कि दुनिया के कमोबेश हर हिस्से में चीजें बहुत जल्दी नियंत्रण से बाहर चली जा रही हैं। इंधन की कीमत में मामूली जिजाफा या यूनिवर्सिटी में फौस बढ़ोतरी किसी सरकार को अस्थिर कर सकती है। सेना सड़कों पर आ सकती है, गोलीबारी, आगजनी व लूटपाट हो सकती है। दुनिया विस्फोटकों से भरा एक डिब्बा हो गई है, जो आग की भट्टी पर चढ़ी है।

लेकिन तब भी ये ढंका हुआ था और ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेडिंग बिजेनेस सभी के लिए नहीं बल्कि कुछ के लिए काम करता था। साल 2000 के दशक में सबसे पहला झटका 2008 की आर्थिक मंदी के रूप में आया, लेकिन ये भी छिपा हुआ ही था। साल 2010 के दशक में भी सब ठीकाक था। लेकिन, इसके बाद दरारें बढ़ने लगीं। ब्रेगिज होने ही बाला था और डोनाल्ड ट्रंप भी अपवाद नहीं हैं। इसके अपने नतीजे हैं, वैश्वीकरण के बाद की दुनिया के इकोनॉमिक ऑर्डर की इच्छा और अनिच्छा से परे। ये सच हैं कि जुनूनी और प्रतिस्पर्धी विकास के इस वक्त में बहुत से लोग हार चुके हैं।



## विकास की कसौटी

इसके अलावा इन दशकों से कुछ सीख भी मिलती है। हम अपनी दुनिया में ग्रामीण संकट और आंतरिक पलायन देख रहे हैं। मैं हर तरह की सतर्कता बरतते हुए कह रही हूं कि क्योंकि मैं जानती हूं कि पलायन और जनसंख्या के आंकड़े हमेशा देर से आते हैं। मैं ऐसा न केवल इसलिए कह रही हूं कि पलायन को लेकर हमेशा बड़े स्तर पर खराब रुख रहता है बल्कि इसलिए भी कह रही हूं कि क्योंकि हमारे शहर अवैध रूप से बढ़ रहे हैं। जो बढ़ोतरी हो रही है, वो असहनीय है। मेरे शहर दिल्ली में कथित अवैध बस्तियों व वहाँ रहनेवाले लोगों की गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वे आते इसलिए हैं कि कुछ नौकरियाँ हैं, जो गांवों की जगह शहरों में मिलती हैं क्योंकि गांवों में किसान खराब बुनियादी ढांचा, कर्ज और खराब मौसम के तिहारे बोझ के नीरे पिस जाते हैं। पलायन करने वालों को नोकरी बिल्कुल निवाले स्तर की मिलती है। अगर हम फैक्टरियों में जाएं (मैं गई हूं), तो देखते हैं कि बदलते व खतरनाक स्थिति में काम कर रहे हैं। वे चारों तरफ से बंद झाँपड़िनुमा जगहों व धूल-धूप में खाते और सोते हैं। ये सब देख कर हमें क्यों यौकना गाहिए? सब ये हैं कि आधुनिक औद्योगिक विकास इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें श्रम, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा पर्यावरण पर होने वाले खर्च के बोझ को उन जगहों पर धकेला जा सकता है, जहाँ रियायतें मिलती हैं।

## वैश्वीकरण के दौर में आत्म केंद्रित

अब दुनिया भी बंट गई है। अब देश साथ मिलकर काम नहीं करते। सभी देश सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पहले स्थितियाँ कुछ अलग थीं। अलवता ये जरूर है कि पहले कुछ दिखावा भी था कि वे एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब वह भी खत्म हो गया है। चूंकि, मौजूदा वक्त में सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर आश्रित हैं, इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। साल 1990 में वैश्वीकरण बहुत सामान्य हो गया था। दुनिया की बेतरी की उम्मीद में अर्थव्यवस्थाएं एक-दूजे से जुड़ गई थीं। उस दशक और उसके बाद के वक्त में इसके खिलाफ आवाजें बुलांद होने लगीं और उद्योगात्मि उन क्षेत्रों की तरफ रुख करने लगे, जहाँ सस्ते मजदूर थे और पर्यावरण प्रबंधन पर खर्च करने से बचा जा सकता था।